प्राकृति सौन्दर्य को गाता एक गांव जेहनगुटूवा

आलोका

झारखण्ड की राजधानी रांची से गुमला 100 कि0 मी0 गुमला से विशुनपूर 22 कि0 मी0, विशूनपूर से जहनगुटूआ 6 कि0 मी0, जेहनगुटूवा बिरहोर के गांव, जिसमें 50 से 55 घर, एक-एक घर में 5 के लगभग आबादी। किसी- किसी घर में 2 और 3 की भी आबादी। यात्रायात के संसाधन से दूर गांव जहां जंगल भाग कर दूर चला गया है, अब पगड़डी के सहारे गांव में घुसने के एक मात्र रास्ते जो प्रधानमंत्री सड़क योजना को ब्यां कर रहा, उस पगड़ी में रास्ते में चलने पर पत्तों की सरसराहट से आगमन की आहट की सूचना गांव में मिलती है गांव में घुसते ही बड़ा सा आदिम जनजाति का विद्यालय जिसमें नाम कही लापता, वहां पूरे विशूनपूर के आदिमजनजाति के बच्चे पढ़ते है पर जेहनगूटूआ के एक भी बच्चा उस स्कूल में नहीं जाता है।

स्कूल की हालत देख कर लगा 100 साल पूराना भूतबंगला पर उसमें ताला लगे हुए थे। दूर दूर तक बांस के घने पौधे उनके झुरमुटी में समाया यह गांव के अन्दर हर दरवाजे पर बैठी महिला और बच्चे, दरवाजे हाथी मार्क तेल के टीने का बना जिसमें सस्सी की बनी छिटकनी से दरवाजा बंद किया गया है इससे लगता है घर के अन्दर कुछ अपनी जरूरत के मंहगे समान होंगे। कुछ दूरी पर गाय बैल बंधा है गांव के बीचों- बीच एक सरकारी चबुतरा जिसमें गांव के लोगो की बैठक की व्यवस्था हाल-हाल में सरकार द्वारा किया गया हो।

कच्ची सड़क कुछ दूर चलने पर जहनगुटवा जहां न पानी, न दवा की व्यवस्था गांव पहुंचने पर बिरहोर के बच्चे बांस के झुड से झांकते और कुडूख भाषा में बाते करते है की गांव में कोई आया है। गांव युवा पुरूष महिलाएं का समूह लाल-लाल, कुर्सी प्लास्टीक के हाथ में लिए चबूतरा के निकट आये और प्रणाम जोहार के साथ बैठने के लिए कहा। गांव में चारो और नजर दौड़ाइ सुख खेत , घूल उड़ाती हवा का झोका, मानों पानी का इंतजार कर रहा खेत। चारों ओर प्राकृति के सौन्दर्य को गाती दिख रही, वादी स्वच्छ सुन्दर दूर भागा वन से स्वच्छ हवा के बीच बिरहोरों की आबादी लगभग 150-200, आजाद भारत के बेरोजगार बिरहोर आधुनिकता से वंचित इसलिए है कि वे बिरहोर जाति से है।

भारत के गांव में रहते है पर भारत के कानून और अपने अधिकार के बारे में जानते नहीं न किसी ने कभी बताया। राजनीति उन्हें आती नहीं आबादी कम होने के कारण राजनीति पार्टी पूछते नहीं इसीलिए वे अपनी समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं कर पाए है स्वास्थ्य केन्द्र गांव में नहीं है गांव में बिमारी होने पर सरकारी अस्पताल अपने पैसे लगाकर जाते है।

2005 में वन कानून बना कि वन के अन्दर रहने वाले को वनभूमि में मालिकाना हक दिया जाएगा वो हुआ नहीं यदि सरकार वन भूमि दे भी देती तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं। शिक्षा अधिकार कानून के तहत करोड़ रूप्ये झारखण्ड में खर्च हो रहे है पर एक पैसा इन बच्चों के पास नही पहुंचा है यदि उन्हें शिक्षा अधिकार के तहत शिक्षत कर भी दिया जाए तो तकनीकी युग में वे फिर से पीछड जाएगे। इस गांव में मिट्टी के घर दूर दूर में बने हुए है हर घर के बाहर एक महिला सिमेंट के बोरा एसीसी को खोलकर रस्सी बना रहीं है। गांव देखकर लगा पहले कभी सरकार से बिरसा आवास बनाया है जिसके छप्पर टीन के चंदरा के बने है। कुछ पक्का घर सरकारी आवास कुछ खपरे के छत ओर कुछ टुटी फूटी मिटटी के घर देख कर लगा बिरहोरो ने अपने मेहनत से बनाया है।

बिरहोर समूदाय के पास अपनी जरूरत के तमाम चीजे, गाय, बैल, बकरी, सरकारी चबुतरा मौजूद है, गांव में आंगनबाड़ी, 32 कि0 चावल प्रति महिना, और 4 लिटर मिट्टी का तेल खुद से डीलर के यहां जाकर अनाज लाते है। जिसके लिए उन्हें भाड़े में 50 रू0 खर्च करना पड़ता है सरकार ने वन भूमि नहीं दिये है जमीन का मालिक अभी बिरहोर हुआ नहीं है। गांव में एक टाटा इस्काई के छतरी, गांव में कई परिवार के पास टीवी और सोलर लाइट की व्यवस्था, गांव के बच्चे और टी बी दोनों धुल से सने हुए सोलर लाइट खराब हो चुका है बिरहोर सोलरा बनाना नहीं जानते है गांव के बुर्जुग जंगल की ओर निकल गये है ,गाय और बकरी लेकर साथ में लाएगे शाम को खाना बनाने के लिए लकड़ी।

युवा अब मजदूर बन गये है वे किसी न किसी के यहां काम करते है पैसा कमाना और परिवार और अपने तमाम तरह की जरूरत की पूर्ति करता। गांव में अब घर के दरवाजे पर ताला लगने लगे है। अपनी सम्पति के चोरी का डर बनता जा रहा है। घर के अंदर बक्सा, जाल, बनी प्लास्टीक की रस्सी, और कुछ चावल, जंगल से चुन कर वन उत्पादन जानवर के अलावा मिट्टी और अल्मूनियम, स्टील के बर्तन के रात में सोने के लिए लेदरा, एक दो कम्बल, चादर मौजूद है पर इनके यहां चटाई नहीं दिखा।

आधुनिकता की उनके जीवन में प्रवेश हो चुका है। घर पर बिमार होने पर स्थानिय अस्पताल जाते है। चैमीन और बाहरी खाद्य समग्री उन्हें पंसद है समय समय पर पैसा होने या स्थानिय मेला या त्योहार में जाते है और उनका प्रयोग करते है। विजय बिरहोर ने बताया की सरकार हमारे योजन को हम तक पहुचने नहीं देती है। हम सब सकक्ष्म नहीं है कि ब्लॉक कार्यालय जाए, महिलाओं के लिए सबसे

अधिक समस्या है वे सरकार के कामकाग के बारे में जानती नहीं है। उन्हें सरकार के योजनाओं के बारे में जान नहीं पाती है और सबसे बड़ी बात की वह अपने घर से ब्लॉक कार्यालय जाने के साधन के अभाव में भी ब्लॉक कार्यालय नहीं जा पाती है। मुख्यधारा में खुद को समाहित करने की चाहत ने तमाम तरह के विकल्प के लिए खड़ा रहना चाहते है।

(सीएसडीएस फेलोसिप के तहत)